ऑनलाइन शिक्षा का मिथक

Field Studies in Education | September 2020



ऑनलाइन शिक्षा का मिथक

शोध समूह | अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन

सम्पर्क : field.research@azimpremjifoundation.org

कार्यकारी सार

कोविड-19 महामारी ने जीवन के हर क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी है। सीखने-सिखाने की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक तरीक़ों की खोजबीन स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे सभी अकादमिक संस्थानों की बाध्यता बन गई है। पिछले छह महीनों में पूरी दुनिया में सीखने के डिजिटल या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जितने भी माध्यमों को आज़माया गया है। इनमें से ज़्यादातर तरीक़े अनुपयुक्त, शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर और वास्तविक संवादों के अपर्याप्त विकल्प ही साबित हुए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में तो ये ख़ासतौर से प्रभावी नहीं रहे हैं क्योंकि स्कूली तालीम के शुरुआती सालों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में गहरी वास्तविक निकटता आवश्यक होती है। यही नहीं, उपकरणों व मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच न होने की वजह से बहुत सारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनसे यह भी पता चलता है कि सीखने के ऑनलाइन तरीक़ों की मान्यता अक्सर बाज़ार-आधारित उपायों की पक्षधरता, शिक्षा के व्यावसायीकरण, और शिक्षकों की पेशेवर क्षमता में अविश्वास व उसमें निवेश की कमी से क़रीब से जुड़ती है।

इस पृष्ठभूमि में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के फ़ील्ड रिसर्च ग्रुप ने एक अध्ययन किया जिसमें **पाँच राज्यों के 26 ज़िलों के 1522 सरकारी स्कूलों के 1522 शिक्षक और 398 अभिभावक शामिल थे।**[1] इन स्कूलों में भारत के सबसे वंचित इलाक़ों के 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि सरकारी स्कूल व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में बच्चे व शिक्षक किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। अध्ययन के दौरान शिक्षकों व अभिभावकों के मामले में प्रश्नावली का इस्तेमाल मुख्यतः टेलीफ़ोन पर बातचीत के ज़रिए किया गया। शिक्षकों के लिए कुछ खुले सवाल (विस्तार से बातचीत वाले) अलग से भी रखे गए।

शिक्षकों व अभिभावकों के सर्वे से पता चला कि सीखने-सिखाने के सार्थक मौक़े देने में ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी नहीं था, इसके लिए ज़रूरी संसाधनों तक पहुँच न होने के चलते अधिकतर बच्चे इससे बाहर हो गए, और शिक्षकों में पेशेवर निराशा भी पनपी (देखें बॉक्स 1)। यह हाल ही में किए गए एक त्वरित सर्वे के नतीजों से मिलता-जुलता है जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि तकनीकी पर निर्भरता और 'डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए क्षमता निर्माण व समर्थन देने में राज्य सरकारों की पूर्ण विफलता' की वजह से सरकारी स्कूलों के 80 प्रतिशत से भी ज़्यादा बच्चे इससे वंचित हुए हैं (व्यास 2020)। हमारे अध्ययन से भी यह पता चलता है कि लोकप्रिय मत के विपरीत ज़्यादातर अभिभावक ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजने को उत्सुक हैं और उनका यह मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होगा।

[1] छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन शिक्षण को लागू किया गया है जबकि कर्नाटक और उत्तराखंड में इस दिशा में कोई राज्य-स्तरीय क़दम नहीं उठाया गया है। इन राज्यों को 'लागू करने वाले राज्य' और 'लागू नहीं करने वाले राज्य' की दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

बॉक्स 1 : महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

निष्कर्ष 1 : सीखने के ऑनलाइन अवसर किसी तरह की वास्तविक शिक्षा देने में प्रभावी नहीं हैं।
शिक्षकों की बड़ी संख्या में मिली प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि सार्थक शिक्षा देने में ऑनलाइन माध्यम बिलकुल अक्षम है।

(1.1) 80 प्रतिशत से ज़्यादा शिक्षकों ने कहा कि इस माध्यम से बच्चों के साथ किसी तरह का भावनात्मक जुड़ाव बना पाना मुश्किल या असंभव है।

(1.2) 90 प्रतिशत से ज़्यादा शिक्षकों ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों के "सीखने का" का सार्थक मूल्यांकन सम्भव नहीं था।

(1.3) लगभग 50 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में दिए गए असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते सीखने में भारी कमी आ रही थी।

(1.4) ऑनलाइन कक्षाओं की आवृति और अवधि के बारे में इकट्ठा किए गए आँकड़ों से यह संकेत मिल रहा है कि इनमें सीखने-सिखाने के लिए बच्चों के साथ लगाया गया समय पर्याप्त नहीं है।

(1.5) इसी तरह, 70 प्रतिशत अभिभावकों की यह राय थी कि बच्चों के सीखने में ऑनलाइन कक्षाएँ प्रभावशाली नहीं थीं।

निष्कर्ष 2 : लगभग 60 प्रतिशत बच्चे सीखने-सिखाने के ऑनलाइन साधनों तक पहुँच पाने में असमर्थ हैं।
इसके कारणों में स्मार्टफ़ोन का अभाव, कई भाई-बहनों द्वारा एक ही स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल किया जाना, ऑनलाइन सीखने के लिए इस्तेमाल होने वाले एप्स को चलाने में परेशानी का सामना करना आदि शामिल हैं। विकलांग बच्चों के मामले में संसाधनों तक पहुँच का मामला और भी गम्भीर हो जाता है। जिन शिक्षकों की नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चे शामिल थे उनमें से 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा शिक्षकों ने यह पाया कि वे बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में समर्थ नहीं थे।

निष्कर्ष 3 : इस अध्ययन में महामारी के चलते सीखने में आई रुकावट के प्रति अभिभावकों के रुख़ और चिन्ताओं को भी समझने की कोशिश की गई। ज़्यादातर अभिभावकों ने ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल खोलने का समर्थन किया है।
लगभग 90 प्रतिशत अभिभावक ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार थे। लगभग 65 प्रतिशत अभिभावकों की राय थी कि स्कूलों के खुलने से उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

अध्ययन के दौरान शिक्षकोंसे विस्तार से बातचीत वाले प्रश्नों के जो जवाब मिले उनसे भी सर्वे के मात्रात्मक नतीजों की पुष्टि होती है। इन जवाबों के विश्लेषण में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण को लेकर शिक्षकों की पेशेवर निराशा साफ़ दिखाई देती है। इन प्रतिक्रियाओं में बच्चों से जुड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा ली जा रही सार्थक वैकल्पिक पहलों का भी पता चलता है जिनके ज़रिए वे अपने बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि नियमित सरकारी स्कूल व्यवस्था स्कूली बच्चों की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बन्द है और उनकी पहुँच से बाहर है।

कुछ राज्यों में ऑनलाइन माध्यमों की अपर्याप्तता को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन विकल्पों को वापस लेकर सीखने-सिखाने के ज़्यादा प्रत्यक्ष तरीक़ों को अपनाया जिनमें शिक्षक स्कूली बच्चों के घर जाकर सम्पर्क करते हैं। ऐसे तरीक़ों में छत्तीसगढ़ की 'पढ़ई तुंहर पारा', मध्य प्रदेश की 'हमारा घर-हमारा विद्यालय' और कर्नाटक की 'विद्यागम' जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

कुल मिलाकर इस अध्ययन के नतीजे हाल के दूसरे अध्ययनों के नतीजों से मिलते-जुलते हैं जिनमें ख़ासतौर से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले स्कूली बच्चों के लिए सीखने के ऑनलाइन उपायों की निरर्थकता को रेखांकित किया गया है। इस सन्दर्भ में यह अध्ययन बच्चों व शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित तैयारी के साथ चरणबद्ध तरीक़े से स्कूलों को दोबारा खोलने की गम्भीर ज़रूरत को स्वीकार करता है। साथ ही, इस दौरान अन्तरिम उपाय बतौर बच्चों के साथ प्रत्यक्ष संवाद के समुदाय-आधारित उपायों को अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने व उनको सहयोग करने की ज़रूरत को भी रेखांकित करता है।



1. प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी और उसके बाद स्कूल व्यवस्था के निष्क्रिय होने से मुख्यधारा की स्कूल व्यवस्था के लिए सीखने के ऑनलाइन उपायों में लोगों की दिलचस्पी में ख़ासी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन वैश्विक (उदाहरण के लिए, वेगास 2020; यूनिसेफ़ 2020) और भारतीय दोनों सन्दर्भों में हाल में हुए अनेक अध्ययनों व रपटों[2] ने यह रेखांकित किया है कि ऐसे परिवेश में जहाँ बुनियादी डिजिटल ढाँचों की उपलब्धता व उन तक पहुँच की स्थिति कमज़ोर है (ख़ासतौर से वंचित समूहों के लिए) और शिक्षकों की तैयारी भी अपर्याप्त है, वहाँ सीखने के ऑनलाइन तौर-तरीक़े अपनाने की बात हवाई क़िले बनाने जैसी है। इस बात के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं कि डिजिटल उपायों को नियमित शिक्षण के विकल्प की तरह नहीं देखा जाना चाहिए (मुकुंदा 2019, पृ. 301-355)। इसके अलावा, डिजिटल व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन सीखने-सिखाने के मॉडलों को व्यावसायिक हितों व बाज़ार-आधारित उपायों के प्रति झुकाव के तानेबाने में रखकर भी देखा जा सकता है।[3]

इस सन्दर्भ में इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि जब अप्रैल 2020 से कई राज्यों के शिक्षा विभागों ने आनन-फ़ानन में सीखने-सिखाने के ऑनलाइन उपायों को अपनाना शुरू कर दिया, तब सरकारी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के सामने क्या कठिनाइयाँ आईं। इस अध्ययन में पाँच राज्यों में सरकारी स्कूलों की बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों व अभिभावकों के साथ टेलीफ़ोन से बातचीत के ज़रिए सर्वे टूल्स का प्रयोग किया गया (तालिका 1)। इन पाँच राज्यों में से तीन — छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान — में पिछले कुछ महीनों से सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन शिक्षण को लागू किया गया है, जबकि कर्नाटक और उत्तराखंड में ऑनलाइन शिक्षण की कोई राज्य-स्तरीय पहल नहीं की गई है।

तालिका 1 : सर्वे में शामिल शिक्षक व अभिभावक

राज्य	ज़िलों की संख्या	शिक्षक	अभिभावक
लागू करने वाले राज्य : छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान	12	634	179
लागू नहीं करने वाले राज्य : कर्नाटक, उत्तराखंड	14	888	219
कुल	26	1522	398

[2] उदाहरण के लिए देखें : स्टेटस रिपोर्ट — गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स ड्यूरिंग कोविड-19 (ऑक्सफ़ैम, इंडिया); आर स्कूल्स इन इंडिया रेडी फ़ॉर ए पोस्ट-कोविड-19 वर्ल्ड? (ड्रीम अ ड्रीम NGO की report); सिनेरियो अमिड्स्ट कोविड-19 : ऑन ग्राउंड सिचुएशंस एंड पॉसिबल सोल्यूशंस (स्माइल फ़ाउण्डेशन)।

[3] उदाहरण के लिए देखें : ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया : 2021 (केपीएमजी और गूगल द्वारा मई 2017 में करवाया गया एक अध्ययन; वेबसाइट - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/05/Online-Education-in-India-2021.pdf.); साथ में यह भी देखें : https://www.india-briefing.com/news/investing-indias-education-market-after-covid-19-new-growth- drivers-20330.html/.

इस अध्ययन से ऑनलाइन सीखने के मॉडलों को लेकर कई गम्भीर सवाल खड़े होते हैं। इनमें डिजिटल सुविधाओं तक बच्चों व परिवारों की सीमित पहुँच, सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं का अल्प व अपर्याप्त स्तर, और साथ में शिक्षकों में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का अपर्याप्त ज्ञान व सीमित इस्तेमाल की समस्या शामिल है जो प्रशिक्षण व समर्थन के अभाव से और भी गहरी हो जाती है।

सम्भवतः राज्य के शिक्षा विभागों को भी ऑनलाइन तरीक़ों के सन्दर्भ में हड़बड़ी में उठाए क़दमों की ग़लती समझ में आने लगी है, क्योंकि अब वे सरकारी स्कूलों के बच्चों से ज़्यादा प्रत्यक्ष संवाद के तरीक़ों की तरफ़ बढ़े हैं जिनमें बच्चों के घरों पर शिक्षकों के भ्रमण और समुदाय-आधारित कक्षाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, अध्ययन में यह भी सामने आया कि उचित सुरक्षा व स्वास्थ्य उपायों के साथ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। यह दोनों तथ्य साफ़ इशारा करते हैं कि सरकारी स्कूलों को जितनी जल्दी हो सके खोलने की ज़रूरत है।

यह अध्ययन आमतौर पर सरकारी स्कूल व्यवस्था में सीखने के ऑनलाइन उपायों से जुड़ी जटिल चुनौतियों को और इसकी बुनियादी असफलता को उभारता है। इस अध्ययन के नतीजे राज्य शिक्षा विभागों द्वारा हाल में लिए गए उन निर्णयों का समर्थन करते हैं जिनमें वास्तविक स्थिति में पारम्परिक तरीक़ों से शिक्षक व बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष संवाद को प्रोत्साहित करने व समर्थन देने की पहल की गई है। साथ ही, यह अध्ययन बच्चों व शिक्षकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित तैयारी के साथ चरणबद्ध तरीक़े से स्कूलों को दोबारा खोलने की गम्भीर ज़रूरत को स्वीकार करता है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे सुचारु रूप से सीख सकें।



2. अध्ययन के नतीजे

2.1 ज़्यादातर बच्चे सीखने के ऑनलाइन अवसरों तक पहुँच ही नहीं सकते

ऑनलाइन माध्यम लागू करने वाले राज्यों में शिक्षकों ने बताया कि नियमित कक्षा में आने वाले 30,511 बच्चों में से मात्र 11,474 बच्चे ही ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे थे। जिन स्कूलों में सर्वे किया गया उनमें औसतन 42 प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि लगभग 60 प्रतिशत बच्चे सीखने के ऑनलाइन अवसरों तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे।

इन राज्यों में ऐसे 110 शिक्षक थे जिनकी नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चे शामिल थे। इनमें से 8 (यानी 7%) शिक्षकों ने ही यह पुष्टि की कि उनकी कक्षा के विकलांग बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भी हाज़िर थे।

शिक्षकों से किए गए सर्वे में यह पूछा गया कि उनके नियमित विद्यार्थियों में से कितने ऐसे थे जिनको ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफ़ोन आसानी से उपलब्ध था। तालिका 2 से पता चलता है कि औसतन 31 प्रतिशत बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफ़ोन आसानी से उपलब्ध था। इसी प्रकार, अभिभावकों के साथ किए गए सर्वे के आँकड़ों से यह पता चलता था कि मोटेतौर पर 87 प्रतिशत अभिभावक ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफ़ोन था, लेकिन महज़ 22 प्रतिशत ही ऐसे थे जिनके पास एक से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन थे। इसका प्रभाव ऑनलाइन शिक्षा तक बच्चों की पहुँच पर पड़ रहा था। इसका संकेत शिक्षकों के साथ हुई चर्चाओं में मिला जिनसे यह पता चला कि ज़्यादातर अभिभावकों को अपने स्मार्टफ़ोन को अपनी काम की जगह पर ले जाना होता है जिसकी वजह से ये बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपलब्ध नहीं रहते।

तालिका 2 : अभिभावकों व बच्चों में स्मार्टफ़ोन की उपलब्धता

	ऑनलाइन शिक्षण लागू करने वाले राज्य	ऑनलाइन शिक्षण नहीं लागू करने वाले राज्य	कुल
शिक्षकों का सर्वे			
नियमित कक्षा में बच्चों की संख्या	30,511	49,577	80,088
जिन बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफ़ोन आसानी से उपलब्ध है	8,650	13,595	22,245
जिन बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफ़ोन आसानी से उपलब्ध है उनका औसत (%)	32	29	31
अभिभावकों का सर्वे			
जिनके पास स्मार्टफ़ोन है (%)	91	85	87
ऐसे अभिभावक जिनके पास एक से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन हैं (%)	20	24	22

लागू करने वाले राज्यों के शिक्षकों ने पहुँच के मुद्दे पर खुले सवालों (विस्तार से बातचीत वाले) के लिए जो प्रतिक्रिया दी उससे सर्वे की चिन्ताओं की पुष्टि होती है (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2 : ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँच के मसले पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया

‘45 मिनट की कक्षा में आधा समय तो “हैलो-हैलो” करने में चला जाता है क्योंकि नेटवर्क ख़राब है और लड़कियों को आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं पड़ती और वे कहती रहती हैं, “मैडम, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है”। इन चार लड़कियों को ही ठीक से पढ़ा पाना मुश्किल होता है अगर सभी छात्राएँ कक्षा से जुड़ जाएँ तो मुझे नहीं पता क्या होगा।’ (रायपुर, छत्तीसगढ़ की एक शिक्षिका)

‘हाज़िरी एक बड़ा मसला है। सिर्फ़ 2-3 बच्चों के साथ कक्षाएँ करना काफ़ी असामान्य है। कुल 14 बच्चों में से सिर्फ़ 4 ही कक्षा से जुड़ सके हैं। नेटवर्क के चलते भी क्लास प्रभावित होती है।’ (धमतरी, छत्तीसगढ़ से एक शिक्षक)

‘सिर्फ़ 20 प्रतिशत अभिभावकों के पास स्मार्टफ़ोन हैं। उनमें से ज़्यादातर मज़दूर हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री तक पहुँच पाना मुश्किल होता है क्योंकि अभिभावक सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। जिनके पास स्मार्टफ़ोन हैं उनमें से आधे बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करने देते, क्योंकि उनको लगता है कि स्मार्टफ़ोन बच्चों के लिए ठीक नहीं है और इससे उनके संस्कार ख़राब होंगे। नेटवर्क भी ख़राब है। आपसे बात करने के लिए मुझे स्कूल से बाहर आना पड़ा। ज़्यादातर परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वे स्मार्टफ़ोन नहीं ख़रीद सकते।’ (टोंक, राजस्थान से एक शिक्षक)

2.2 सीखने के ऑनलाइन अवसर किसी तरह की वास्तविक शिक्षा देने में प्रभावी नहीं हैं

दोनों श्रेणी के राज्यों (ऑनलाइन शिक्षण पद्धति लागू करने वाले और नहीं लागू करने वाले) के शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव बना पाने को लेकर चिन्ता ज़ाहिर की (तालिका 3)। लागू करने वाले राज्यों के 84 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव बना पाना मुश्किल या असम्भव था। दूसरी तरफ़, नहीं लागू करने वाले राज्यों के 89 प्रतिशत शिक्षकों ने चिन्ता ज़ाहिर की कि उनके राज्य में ऑनलाइन शिक्षा लागू होने की स्थिति में भी ऐसा ही होगा।

तालिका 3 : ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव

	लागू करने वाले राज्य		लागू नहीं करने वाले राज्य		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाना आसान	102	16	102	11	204	13
बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाना मुश्किल या असम्भव	532	84	786	89	1,318	87

लागू करने वाले राज्यों के शिक्षकों ने ऑनलाइन सीखने-सिखाने के मुद्दे पर खुले सवालों (विस्तार से बातचीत वाले) के लिए जो प्रतिक्रिया दी उसमें भी ऐसी ही चिन्ताएँ देखने को मिलीं (बॉक्स 3)।

बॉक्स 3 : ऑनलाइन सीखने-सिखाने के मसले पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया

'यह ज़्यादातर एक-तरफ़ा बातचीत होती है; हम पीपीटी बनाते हैं और वीडियो व तस्वीरें शेयर करते हैं। लेकिन यह जानना मुश्किल होता है कि कितने बच्चों को यह समझ में आ रहा है। यह देखकर भी बुरा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे कक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इन बच्चों का क्या होगा हमें नहीं पता। हम वॉट्सएप पर पढ़ने की कुछ सामग्री और होमवर्क भी शेयर करते हैं जिसे कुछ बच्चे पूरा करके वापस भेजते हैं। अब तो ज़्यादातर बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें भी नहीं हैं; सिर्फ़ कुछ के पास ही उनके भाई-बहनों या आस-पड़ोस के बच्चों की किताबें हैं।' (रायपुर, छत्तीसगढ़ से एक शिक्षक)

'मैं गणित से जुड़ी सामग्री भेजता हूँ। गणित में किसी अवधारणा का वीडियो देखना तो ठीक है मगर इस विषय में अभ्यास की ज़रूरत होती है। बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभ्यास के लिए उनके साथ किसी का होना ज़रूरी है।' (टोंक, राजस्थान से एक शिक्षक)

'हर बच्चा अलग होता है। अगर मेरे तीन बच्चे हैं जिनकी तीन अलग चीज़ों में रुचि है तो मैं उनकी रुचि के अनुसार उनको प्रेरित करती हूँ। हमें गतिविधियों के ज़रिए पढ़ाना होता है। यह काम फ़ोन पर कैसे होगा? किसी वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा और शिक्षक की भाषा में फ़र्क़ होता है। वे [बच्चे व अभिभावक] वैसी भाषा नहीं समझ सकते। हमें केन्द्र [राज्य के कार्यालय] से सामग्री मिलती है जिसे हमें बच्चों को भेजना होता है। हम अपने बच्चों के लिए ख़ुद सामग्री नहीं बनाते। अब भला इतनी दूर बैठा कोई व्यक्ति मेरे बच्चों के लिए सामग्री कैसे बना सकता है? ये [ऑनलाइन सामग्री] मेरे बच्चों की पृष्ठभूमि से बिलकुल अलग है।' (बाड़मेर, राजस्थान से एक शिक्षक)

लागू करने वाले राज्यों में 90 प्रतिशत शिक्षकों (आधार संख्या = 634) ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चे क्या सीख रहे हैं इसका कोई सार्थक मूल्यांकन शिक्षक नहीं कर पा रहे थे। बाक़ी के 10 प्रतिशत शिक्षकों में से भी आधे ने यह स्वीकार किया कि ऑनलाइन कक्षा में सार्थक मूल्यांकन करना कठिन है।

शिक्षकों से यह पूछा गया कि ऑनलाइन कक्षाओं में क्या बच्चों को कोई असाइनमेंट दिया गया। लागू करने वाले राज्यों में लगभग 17 प्रतिशत (आधार संख्या = 548) शिक्षकों ने बच्चों को कोई असाइनमेंट नहीं दिया था। जिन शिक्षकों ने असाइनमेंट दिया भी था (आधार संख्या = 456) उनमें से 44 प्रतिशत ने बताया कि बच्चे ये असाइनमेंट पूरा नहीं कर सके थे।

अभिभावकों के सर्वे में कुछ ऐसी चिन्ताएँ ज़ाहिर हुईं जिनसे शिक्षकों द्वारा बताई गई उपर्युक्त स्थितियों की वजह को समझने में मदद मिल सकती है। लागू करने वाले राज्यों में 36 प्रतिशत (आधार संख्या = 124) ने बताया कि उनके बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में इस्तेमाल होने वाले एप्स का इस्तेमाल ख़ुद नहीं कर सकते थे।

अभिभावकों से यह भी पूछा गया कि ऑनलाइन कक्षाएँ उनके बच्चों के लिए कितनी उपयुक्त हैं। लागू करने वाले राज्यों में लगभग 70 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन कक्षाएँ बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं लगीं। लागू नहीं करने वाले राज्यों में 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा अभिभावकों ने कहा कि उनका मानना था कि ऑनलाइन कक्षाएँ उनके बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होंगी (तालिका 4)।

तालिका 4 : ऑनलाइन कक्षाएँ कितनी उपयुक्त हैं

	लागू करने वाले राज्य		लागू नहीं करने वाले राज्य		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ऑनलाइन कक्षाएँ बच्चों के लिए उपयुक्त हैं	42	31	78	46	120	39
ऑनलाइन कक्षाएँ बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं	93	69	93	54	186	61

2.3 सीखने-सिखाने के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल के लिए शिक्षकों की तैयारी पर्याप्त नहीं है

भारत के सरकारी स्कूलों में हीं नहीं, बल्कि समूचे स्कूल व्यवस्था में ही सीखने-सिखाने के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन शिक्षण के तरीक़ों का इस्तेमाल नियमित रूप से नहीं होता है। आधे से अधिक शिक्षकों (मोटेतौर पर 54 प्रतिशत) ने यह माना कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्मों व शिक्षण के तरीक़ों का उनका ज्ञान व अनुभव पर्याप्त नहीं है (तालिका 5)।

तालिका 5 : शिक्षकों में सीखने-सिखाने के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों की जानकारी

	लागू करने वाले राज्य		लागू नहीं करने वाले राज्य		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों की पर्याप्त जानकारी का अभाव	334	53	493	56	827	54
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों की पर्याप्त जानकारी	300	47	395	44	695	46

2.4 ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रियाएँ

शिक्षकों के सर्वे से यह भी पता चला कि ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षकों व बच्चों के परस्पर संवाद कम ही था। ऐसे शिक्षक जो ऑनलाइन कक्षा में बच्चों से रोज़ सम्पर्क कर रहे थे उनकी संख्या लगभग 50 प्रतिशत ही थी। बाक़ी के शिक्षक रोज़ बच्चों से संवाद नहीं कर रहे थे (तालिका 6)।

तालिका 6 : ऑनलाइन कक्षाओं की आवृति

	शिक्षक (%)	अभिभावक (%)
रोज़ाना	49	49
हर दूसरे दिन	17	17
हफ़्ते में दो दिन	14	6
हफ़्ते में एक दिन	12	0
15 दिन में एक बार	2	4
कोई निश्चित आवृति नहीं	7	25

शिक्षकों के सर्वे से यह भी पता चला कि अमूमन 75 प्रतिशत शिक्षक किसी भी कक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल औसतन 1 घण्टे प्रतिदिन से भी कम समय के लिए कर रहे थे (तालिका 7)। शिक्षकों और अभिभावकों दोनों की प्रतिक्रियाओं से यह लगता है कि 80 प्रतिशत मामलों में शिक्षकों द्वारा किसी भी कक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल औसतन 1 घण्टा प्रतिदिन या उससे भी कम समय के लिए किया जाता है।

तालिका 7 : ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षण का औसत समय

	शिक्षक (%)	अभिभावक (%)
1 घण्टा प्रतिदिन से कम	74	20
1 घण्टा प्रतिदिन	24	64
1 घण्टा प्रतिदिन से अधिक	2	16

लागू करने वाले कुछ राज्यों में 24 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सीखने-सिखाने की कोई सामग्री साझा नहीं की जबकि 24 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने कक्षाओं में ऐसी सामग्री शेयर की। इसके परिणामस्वरूप ज़्यादातर ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों के पास कक्षा से पहले कोई भी शिक्षण सामग्री नहीं थी।

लागू करने वाले राज्यों में सामग्री शेयर करने का मुख्य ज़रिया वॉट्सएप था जिसका इस्तेमाल 71 प्रतिशत शिक्षक कर रहे थे। लगभग 14 प्रतिशत शिक्षक एमएस टीम्स, ज़ूम और वेबएक्स जैसे दूसरे एप्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे।

2.5 स्कूल खोले जाने पर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं

अभिभावकों के सर्वे में हमने पूछा कि स्कूल खोले जाने पर क्या अभिभावक अपने बच्चों को ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल भेजने को तैयार हैं। लोकप्रिय धारणा के उलट, ज़्यादातर अभिभावक (कुल 90 प्रतिशत) ऐसा करने को तैयार थे (तालिका 8)।

तालिका 8 : स्कूल खोले जाने पर बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक अभिभावक

	लागू करने वाले राज्य		लागू नहीं करने वाले राज्य		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
नहीं भेजना चाहते हैं	2	1	30	18	32	10
भेजना चाहते हैं	133	99	141	82	274	90

इस बात को लगभग 66 प्रतिशत ऐसे अभिभावकों की राय से भी बल मिलता है जिनका मानना था कि स्कूल जाने से उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा (तालिका 9)।

तालिका 9 : स्कूल खुलने की स्थिति में वहाँ बच्चों के सुरक्षित होने के बारे में अभिभावकों की राय

	लागू करने वाले राज्य		लागू नहीं करने वाले राज्य		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
स्कूल सुरक्षित नहीं हैं	44	38	42	30	86	34
स्कूल सुरक्षित हैं	71	62	98	70	169	66

3. निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में भारत तथा वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययनों ने यह रेखांकित किया है कि इस दौर में सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल से असमानताएँ तेज़ी से बढ़ सकती हैं। बुनियादी स्कूली शिक्षा तक पहुँच में जिस तरह की असमानताएँ आज हैं और इनकी बुनियाद में जिस तरह के सामाजिक-आर्थिक विभेद मौजूद हैं उनके सन्दर्भ में कोई आश्चर्य नहीं है कि सीखने-सिखाने के ऑनलाइन उपायों से स्कूली शिक्षा में यह असमानताएँ और बढ़ेंगी।

कुल मिलाकर, इस अध्ययन के नतीजे हाल में किए गए ऐसे दूसरे अध्ययनों के नतीजों से मिलते-जुलते हैं जो विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा से सरकारी स्कूलों के बच्चों के सामने पैदा हुई गंभीर समस्याओं को रेखांकित करते हैं। ये समस्याएँ हैं — ऑनलाइन सीखने के माध्यमों तक ग़रीब परिवारों व बच्चों की अत्यन्त सीमित पहुँच, सीखने के समुचित अवसर देने में ऑनलाइन शिक्षण का प्रभावी न होना, और ऑनलाइन शिक्षण के लिए शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी। इस अध्ययन से महामारी के शुरुआती दौर में कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए ऑनलाइन उपायों की अपर्याप्तता का भी पता चलता है। ख़ुशक़िस्मती से इनमें से कई पहलों को वापस ले लिया गया है और राज्यों के शिक्षा विभागों ने ज़्यादा परिवेश-आधारित, प्रत्यक्ष शिक्षण के तरीक़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। यह तथ्य भी इस अध्ययन में मिले इन नतीजों के अनुरूप है जिनके अनुसार अभिभावक न सिर्फ़ ऑनलाइन शिक्षण से असन्तुष्ट हैं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के समुचित उपायों के साथ उनको स्कूल भेजने को तत्पर भी हैं।

इस सन्दर्भ में, यह अध्ययन बच्चों व शिक्षकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित तैयारी के साथ चरणबद्ध तरीक़े से स्कूलों को दोबारा खोलने की तात्कालिक ज़रूरत को स्वीकार करता है। साथ ही, यह अध्ययन स्कूलों को चरणबद्ध खोले जाने के अन्तरिम दौर में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति में परिवेश-आधारित, सीखने-सिखाने के प्रत्यक्ष तरीक़ों को अपनाने की सलाह भी देता है।

सन्दर्भ

मुकुंदा, के, वी 2019, व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे?, नोएडा : हार्पर कोलिंस

यूनिसेफ़, 2020, कोविड-2019: आर स्कूल चिल्ड्रेन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोज़र्स?, न्यूयॉर्क : यूनिसेफ़

वेगास, एमिलियाना, 2020, स्कूल क्लोज़र्स, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज़, एंड लर्निंग इनइक्वालिटी सराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19, (वेबसाइट - https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/)

व्यास, ए, 2020, स्टेटस रिपोर्ट – गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स ड्यूरिंग कोविड-19, ऑक्सफ़ैम, इंडिया





Azim Premji University

Pixel Park, PES Campus, Electronic City, Hosur Road, Bangalore 560100

080-6614 5136

www. azimpremjiuniversity.edu.in

Facebook: /azimpremjiuniversity **Instagram:** @azimpremjiuniv **Twitter:** @azimpremjiuniv